कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र),जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

सकारण आदेश/SPEAKING ORDER
(स्थापना आदेश संख्या:- सीसीयू- 35/2026)
Establishment Order No:- CCU- 35/2026
दिनांक :-ई-हस्ताक्षर के अनुसार
Dated:-As per E-signature

(माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर मूल आवेदन संख्या 2795/2024 से उत्पन्न/Arising out of O.A. No. 2795/2024 filed in the Hon'ble CAT, Pr. Bench, New Delhi)

मामले के संक्षिप्त तथ्य/BRIEF FACTS OF THE CASE:-

उपरोक्त मूल आवेदन श्री गजेन्द्र सिंह नेवारी, सहायक आयुक्त (अब सेवानिवृत) एवं 67 अन्य आवेदकों द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर किया गया | इस मूल आवेदन में सम्मिलित मुख्य मुद्दा यह है कि क्या आवेदक पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500–12000, जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन संरचना ₹9300–34800 में ग्रेड पे ₹4800 (PB-2) के समकक्ष है, में चार वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर, पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹8000–13500, जो संशोधित वेतन संरचना ₹9300–34800 में ग्रेड पे ₹5400 (PB-2) के समकक्ष है, में स्थानांतरण (placement) के हकदार हैं या नहीं, भले ही उक्त वेतनमान उन्हें नियमित पदोन्नति के माध्यम से नहीं बल्कि एसीपी/एमएसीपी (ACP/MACP) के माध्यम से प्राप्त हुआ हो, तथा इसके साथ सभी परिणामी लाभ (consequential benefits) भी प्रदान किये जाये।

The aforesaid O.A. was filed by Shri Gajendra Singh Newari, Assistant Commissioner (now retired) & 67 other applicants in the Hon'ble CAT, Pr. Bench, New Delhi. The issue involved in this O.A. is as to whether the applicants are entitled for placement in the pre-revised scale of pay Rs. 8000-13500 corresponding to revised pay structure Rs. 9300-34800 in

Grade Pay Rs. 5400/- in PB-2 on completion of regular service of four years in the pre-revised scale of pay Rs. 7500-12000 corresponding to revised pay structure Rs. 9300-34800 in Grade Pay Rs. 4800/- in the Sixth Central Pay Commission pay scales even if it has been attained on ACP/MACP and not by way of regular promotion, with all consequential benefits.

2. अधिकरण ने उपरोक्त मूल आवेदन का निस्तारण आदेश दिनांक 07.08.2025 के द्वारा, निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया है:-

The Tribunal has disposed of the aforesaid O.A. vide Order dated 07.08.2025 with following directions:-

> *"8. While doing so, the respondents shall not deny the relief solely on the ground that earlier judgments were rendered in personam. The principles laid down in OA No. 1944/2016 and M. Subramaniam are to be treated as in rem and uniformly applicable in such service matters."*

3. चूँकि मामलें में निहित विषय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और बोर्ड द्वारा निर्मित नीति से संबंधित है, अतः बोर्ड ने जांच के पश्चात, पत्र F.No. A-23011/44/2020-Ad IIA-Part (2) दिनांक 03 सितम्बर 2025 के माध्यम से निर्देश दिया कि अधिकरण के उपरोक्त आदेश को, केवल व्यक्तिगत आवेदकों के संदर्भ में, इन पर्सोनम आधार पर सकारण आदेश जारी करते हुए लागू किया जाये, बशर्ते कि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के आदेश, जो कि डब्ल्यू.पी. सं. 13225/2010- एम. सुब्रमण्यम मामले में पारित हुआ है एवं जिसके विरुद्ध दायर SLP को खारिज किया गया था, से तथ्यात्मक रूप से समान हो।

Since, the issue involved in the matter is related to the policy formulated by the DoPT & the Board, the Board after examination vide letter F.No. A-23011/44/2020-Ad.IIA-Part(2) dated 03.09.2025 has directed to implement the aforementioned Order of the Tribunal in respect of the individual applicants on in personam basis only, by way of issuing the speaking order provided that the cases are similar to the case covered in the Hon'ble Madras High Court order dated 06.09.2010 in W.P. No. 13225/2010 passed in M. Subramaniam case against which SLP was dismissed.

<u>चर्चा एवं निष्कर्ष/DISCUSSION AND FINDINGS:-</u>

4. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), प्रधान पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में, इस मामले का गहन परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री गजेन्द्र सिंह नेवारी, सहायक आयुक्त (सेवानिवृत) एवं 67 अन्य आवेदकों ने

प्रतिवादियों को निर्देश जारी करने हेतु माननीय अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन (O.A.) दायर किये हैं, ताकि उन्हें पीबी-2 में ग्रेड पे ₹4800 में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर पीबी-2 में ग्रेड पे ₹5400 का लाभ प्रदान किया जा सके।

In pursuance to aforesaid Order of the Hon'ble CAT Pr. Bench, New Delhi, matter has been thoroughly examined and it is observed that Shri Gajendra Singh Newari, Assistant Commissioner (Retired) alongwith 67 other applicants has filed O.A. before the Hon'ble Tribunal for issuance of directions to the respondents to extend the benefit of grade of Rs. 5400 /- in PB-2 upon completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4800 in PB-2.

5. गैर-कार्यात्मक ग्रेड प्रदान करने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों तथा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

The instructions regarding grant of Non-Functional Grade issued by the DoP&T and CBIC from time to time as well as various orders passed by the Hon'ble CAT/Courts are, briefed as under:

5.1 छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए विभिन्न सिफारिशें दीं। सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों को दिनांक 29 अगस्त 2008 को GSR 622(E) के माध्यम से केंद्रीय सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम, 2008, में अधिसूचित किया गया। केंद्रीय सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियमों के पार्ट- सी के भाग II के अनुसार सूचित किया गया कि अधिसूचना के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों के लिए कॉलम (5) और (6) में उल्लिखित संशोधित वेतन संरचना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त अधिसूचना के भाग II में, क्र. सं. 9 के अंतर्गत, 'वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग' के शीर्षक के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि आयकर अधिकारी/अधीक्षक/मूल्यांकक आदि (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) को वेतनमान ₹7500–12000 (पूर्व-संशोधित) में पे बैंड–2, ग्रेड पे ₹4,800/- के साथ रखा जाये। इसके अतिरिक्त उल्लेख किया गया है कि 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद उन्हें ₹8000–13500 में संशोधित वेतनमान, पे बैंड–2 के साथ ग्रेड पे ₹5,400/- में रखा जायेगा। नियमों की प्रथम अनुसूची के भाग A के सेक्शन I में, समूह 'A', 'B', 'C' और 'D' में वेतनमान वाले पदों के लिए संशोधित वेतनबैंड और ग्रेड पे प्रदान किये गये हैं, सिवाय उन पदों के जिनके लिए अलग से संशोधित वेतनमान अधिसूचित किया गया है। इसके अनुसार, पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500–12000 वाले कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना ₹9300–34800 के वेतनबैंड में, ग्रेड पे ₹4,800/- के साथ निर्धारित की गई है।

The 6th Central Pay Commission gave various recommendations for fixing of pay of employees of the Government of India. The recommendations accepted by the Government were notified vide GSR 622 (E) dated 29th August 2008 as Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008. As per Section II of Part-C of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, it was informed that the revised pay structure mentioned in Column (5) and (6) of this part of the Notification for the posts mentioned in Column (2) have been approved by the Government. In Section – II of the said Notification, it is laid down against Sl. No. 9, under the Head 'Department of Revenue, Ministry of Finance' that Income Tax Officers/Superintendents/Appraisers etc. (Customs & Central Excise) be placed in the Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised) in Pay Band–2 with Grade Pay of Rs. 4,800/-. Further it has been mentioned that they will be placed in Revised Pay Scale of Rs. 8,000–13,500 in PB-2 with Grade Pay of Rs. 5,400/- after 4 years. Section I of Part A of the First Schedule to the Rules, provides the Revised Pay Bands and Grade Pays for posts carrying scales in Group 'A,' 'B,' 'C' & 'D' except posts for which different revised scales are notified separately. As per the same, the revised pay structure for employees in the Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised) has been rectified as Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,800/-.

5.2 वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 नवंबर 2008 को पत्रांक F. No. A. 26017/98/2008-Ad.IIA मे केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008, भाग C, सेक्शन II का संदर्भ दिया, जिसमें 'वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग' के शीर्षक के अंतर्गत क्र. सं. 9 में यह दर्शाया गया है कि अधीक्षक, मूल्यांकक आदि (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) [जो पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500–12000 में हैं] को 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद PB-2 में ग्रेड पे ₹5,400/- प्रदान किया जायेगा [जो पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹8000–13500 के अनुरूप है]। इसके अतिरिक्त, व्यय विभाग संकल्प (Department of Expenditure Resolution) दिनांक 29 अगस्त 2008 के पैरा 1 की उपधारा (x)(e) में भी यह संकेत दिया गया है कि "डाक, राजस्व आदि विभागों के समूह-बी अधिकारी नियमित रूप से ग्रेड पे ₹4,800/- में PB-2 में 4 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत गैर-कार्यात्मक आधार पर PB-2 में ग्रेड पे ₹5,400/- प्राप्त करेंगे।" मंत्रालय ने अपने पत्रांक दिनांक 21 नवंबर 2008 के अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया कि व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने स्पष्ट किया है कि 4-वर्ष की अवधि की गणना उस तिथि से की जायेगी जिस दिन किसी अधिकारी को ₹7,500-12,000 (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में रखा गया हो।

The Ministry, vide letter under F. No. A. 26017/98/2008-Ad.IIA dated 21st November 2008, referred to Part – C, Section – II of the CCS (Revised Pay) Rules, 2008, wherein under the heading of 'Ministry of

Finance, Department of Revenue' at Sl. No. 9, it is indicated that Superintendents, Appraisers, etc. (Customs and Central Excise) [who are in the pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000] shall be granted Grade Pay of Rs. 5,400/- in PB-2 [corresponding to pre-revised scale of Rs. 8,000-13,500], after 4 years of service. Further, in Clause (x)(e) of Para 1 of the RESOLUTION of the Department of Expenditure dated 29th August 2008 also it was indicated that "*Group-B Officers of Departments of Posts, Revenue etc. will be granted Grade Pay of Rs. 5,400/- in PB-2 on non-functional basis after 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in PB-2.*" The Ministry in Para 3 of aforesaid letter dated 21st November 2008, stated that the Department of Expenditure has clarified that the 4-years period is to be counted with effect from the date on which an officer is placed in the Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised).

5.3 इसके अलावा, मंत्रालय ने दिनांक 11 फरवरी 2009 के पत्रांक F. No. A.26017/98/2008-Ad.IIA के अनुच्छेद 3 में इस विषय पर स्पष्ट किया कि मामले की जांच व्यय विभाग (Department of Expenditure) के परामर्श से की गई, जिन्होंने इस विषय पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:-

Further, the Ministry vide Para 3 of letter F. No. A.26017/98/2008-Ad.IIA dated 11th February 2009, on the issue clarified that the matter has been examined in consultation with the Department of Expenditure who have clarified the matter as under:-

"…. Non-functional upgradation to the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Pay Band PB-2 can be given on completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in PB-2 (pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000) after regular promotion and not on account of financial upgradation due to the ACP."

5.4 माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ ने दिनांक 19 अप्रैल 2010 के अपने आदेश के माध्यम से मूल आवेदन संख्या 167/2009, जिसमें ग्रेड पे ₹5400/- और इसके अनुषंगिक लाभ 01 जनवरी 2008 से प्राप्त करने की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया था, जो कि भारत सरकार द्वारा छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6th CPC) की सिफारिशों को स्वीकार करने के आदेशों के अनुसार था। उक्त मूल आवेदन के खारिज किये जाने से असंतुष्ट होकर, श्री एम. सुब्रमण्यम ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 13225/2010 दायर की। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 06 सितंबर 2010 के अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:-

The Hon'ble CAT, Madras Bench, vide its order dated 19th April 2010 had dismissed the O.A. No. 167/2009 seeking grant of Grade Pay of Rs. 5,400/- and the consequential benefits with effect from 01st January 2008 as per the orders of the Government of India accepting the recommendations of the 6th CPC. Being aggrieved by the dismissal of the aforesaid O.A., Shri M. Subramaniam filed W.P. No. 13225 of 2010 before the Hon'ble High Court of Judicature at Madras. The Hon'ble High Court of Judicature at Madras, vide order dated 06th September 2010, made the following observations:-

> *"7. We are unable to agree with this clarification given by the Under Secretary to the Government of India, since in an earlier clarification dated 21.11.2004 (correct date 21.11.2008) of the Deputy Secretary to Government of India, it was clarified as to how the 4-year period is to be counted for the purpose of granting non-functional upgradation to Group-B Officer, i.e. whether the 4-year period is to be counted with effect from the date on which the officer is placed in the pay scale of Rs. 7,500-12000 (pre-revised) or with effect from 01.01.2006, i.e. the date on which the recommendation of the 6th CPC came into force. It was clarified that the 4-year period is to be counted with effect from the date on which an officer is placed in the pay scale of Rs. 7,500-12000 (pre-revised).*
>
> *8. Thus, if an officer has completed 4 years on 01.01.2006 or earlier, he will be given the non-functional upgradation with effect from 01.01.2006 and if the officer completes 4-years on a date after 01.01.2006, he will be given non-functional upgradation from such date on which he completes 4-year in the pay scale of Rs. 7,500-12,000/- (pre-revised), since the petitioner admittedly completed 4-year period in the pay scale of Rs. 7500-12000 as on 01.01.2008, he is entitled to the grade pay of Rs. 5400/-. In fact, the Government of India having accepted the recommendations of the 6th Pay Commission, issued a resolution dated 29.08.2008 granting grade pay of Rs. 5400/- to Group B officers in Pay Band-2 on non-functional basis after four years of regular service in the grade pay of Rs. 4800/- in Pay Band-2. Therefore, denial of the same benefit to the petitioner based on the clarification issued by the Under Secretary to the Government of India was contrary to the above said clarification and without amending the rules of the revised pay scale, such decision cannot be taken. Therefore, we are inclined to interfere with the order of the Tribunal.*

> 9. *Accordingly, the Writ Petition is allowed setting aside the order of the Tribunal, dated 19.4.2010 passed in O.A. No. 167 of 2009. The respondents are directed to extend the benefit of grade pay of Rs. 5,400/- to the petitioner from 01.01.2008 as per the resolution dated 29.08.2010 (correct date 29.08.2008).”*

5.5 व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने दिनांक 29 अगस्त 2008 के संकल्प संख्या 1/1/2008-IC के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि राजस्व विभाग के समूह 'B' के अधिकारियों को PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में चार वर्ष नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात PB-2 में गैर-कार्यात्मक आधार पर ग्रेड पे ₹5400/- प्रदान किया जायेगा। सुविधा के लिए व्यय विभाग द्वारा 29 अगस्त 2008 के संकल्प का अनुच्छेद 1(x)(e) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

Department of Expenditure, vide Resolution No. 1/1/2008-IC dated 29th August 2008, has specified that the Group 'B' officers of the Department of Revenue will be granted Grade Pay of Rs. 5,400/- in Pay Band–2 on non-functional basis after 4 (four) years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in Pay Band– 2. Para 1(x)(e) of the resolution dated 29th August 2008 issued by the Department of Expenditure is reproduced below for the sake of convenience :-

> “*Group 'B' officers of Department of Posts, Revenue etc. will be granted grade pay of Rs. 5400/- in PB-2 on non-functional basis after 4 years of regular service in the grade of Rs. 4800/- in PB-2.”*

5.6 इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (अब केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के क्षेत्रीय गठन से यह संदर्भ प्राप्त होने पर कि क्या वे अधिकारी जिन्होंने ACP के तहत वित्तीय उन्नयन के कारण पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500-12000 प्राप्त किया है, उन्हें भी निर्धारित वेतनमान ₹7500-12000 (पूर्व-संशोधित) में 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार द्वारा स्वीकार की गई छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6th CPC) की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त गैर-कार्यात्मक उन्नयन का लाभ मिलेगा या नहीं, इस विषय को पुनः व्यय विभाग (Department of Expenditure) के परामर्श से विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया और निम्नानुसार स्पष्ट किया गया:-

Further, on receipt of some other references from field formations of CBEC (now CBIC) as to whether the officers who have got the pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000 by virtue of financial upgradation under ACP will also be entitled to the benefit of further non-functional upgradation on completion of 4 years in the prescribed

Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised) in terms of the recommendations of the 6th CPC as accepted by the Government, the matter was again examined at length in consultation with the Department of Expenditure and it was clarified as under :-

".....Non-functional upgradation to the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Pay Band PB-2 can be given on completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in PB-2 (pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000) after regular promotion and not on account of financial upgradation due to ACP."

इसके अनुरूप, इस संदर्भ में स्पष्टीकरण बोर्ड के पत्रांक F. No. A.26017/98/2008-Ad.II.A दिनांक 11.02.2009 के माध्यम से जारी किया गया।

Accordingly, a clarification to this effect was issued vide Board's letter F. No. A.26017/98/2008-Ad.II.A dated 11.02.2009.

5.7 उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश की जांच की गई और श्री एम. सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ मामले में व्यय विभाग (Department of Expenditure) के परामर्श से समूह 'B' अधिकारियों को PB-2 में ग्रेड पे ₹5400/- में गैर-कार्यात्मक ग्रेड प्रदान करने के संबंध में दिनांक 11.02.2009 के स्पष्टीकरण के आधार पर समीक्षा की गई।

In view of the above facts, the order of the Hon'ble High Court of Judicature at Madras was examined in light of clarification dated 11.02.2009 on grant of Non-functional grade in the Grade Pay of Rs. 5,400/- in PB-2 to Group 'B' officers in consultation with Department of Expenditure in the case of Shri M. Subramaniam Vs. Union of India.

5.8 व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने UO संख्या 15(23)E.III(B)/2010 दिनांक 24.12.2010 के माध्यम से स्पष्ट किया कि PB-2 वेतन बैंड में ग्रेड पे ₹5,400/- में गैर-कार्यात्मक उन्नयन केवल तब दिया जा सकता है जब अधिकारी ने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- (पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7,500–12,000) में नियमित सेवा के 4 वर्ष पूर्ण कर लिये हों, और यह नियमित पदोन्नति के आधार पर होना चाहिए, सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना के आधार पर नहीं। श्री एम. सुब्रमण्यम के मामले में, वह निरीक्षक के पद पर तैनात थे और उन्हें सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना के तहत PB-2 में ग्रेड पे ₹4,800/- प्रदान

किया गया था। उन्हें अधीक्षक/मूल्यांकक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था और इसलिए उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे ₹4,800/- में कोई नियमित सेवा नहीं दी थी। अतः उन्हें PB-2 में ग्रेड पे ₹4,800/- में 4 वर्ष सेवा पूर्ण करने के बाद ग्रेड पे ₹5,400/- का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भी व्यय विभाग के इस दृष्टिकोण को अनुमोदित किया।

Department of Expenditure, vide UO No. 15(23)E.III(B)/2010 dated 24.12.2010, clarified that non-functional upgradation to the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Pay Band PB-2 can be given on completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in PB-2 (pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000) after regular promotion and not on account of financial upgradation due to ACP. In the case of Shri M. Subramaniam, he was holding the post of Inspector and was granted the Grade Pay of Rs. 4,800/in PB-2 under ACP Scheme. He was not promoted to the post of Superintendent/Appraiser and as such, he had not rendered any regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/-. Therefore, he could not be extended the benefit of the Grade Pay of Rs. 5,400/- after 4 years of service in the Grade Pay of Rs. 4,800/-. DoP&T also endorsed the view of the Department of Expenditure.

5.9 अतः, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के आदेश (रिट याचिका सं. 13225/2010) के खिलाफ, भारत संघ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP संख्या 15627/2011 दायर की गई (जिसे बाद में सिविल अपील संख्या 8883/2011 में परिवर्तित किया गया)। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2017 के अपने आदेश में विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और तदनुसार अपील और भारत संघ द्वारा दायर SLP को खारिज कर दिया।

Accordingly, an SLP No. 15627 of 2011 was filed before the Hon'ble Supreme Court (subsequently converted to Civil Appeal No. 8883/2011) against the Hon'ble Madras High Court's Order dated 06.09.2010 in W.P. No. 13225/2010. The Hon'ble Supreme Court, vide order dated 10.10.2017, did not see any ground to interfere with the impugned order and, accordingly, dismissed the appeal and the SLP filed by the Union of India.

5.10 इसके पश्चात, भारत संघ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 8883/2011 में समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 2512/2018 भी दायर की,

जिसे 23.08.2018 के आदेश के माध्यम से, विलंब और याचिका की सामग्री (merits) दोनों आधारों पर खारिज कर दिया गया।

Thereafter, a Review Petition (Civil) No. 2512 of 2018 in Civil Appeal No. 8883 of 2011 was also filed by the Union of India before the Hon'ble Supreme Court, which was also dismissed vide order dated 23.08.2018, on the ground of delay as well as on merits.

6. इस प्रकरण में सम्मिलित विषय नीति से संबंधित है, अतः बोर्ड द्वारा परीक्षण के पश्चात, पत्र संख्या F. No. A-23011/44/2020-Ad.IIA (भाग-2) दिनांक 03 सितम्बर 2025 के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अधिकरण के उपरोक्त आदेश को केवल इन पर्सोनम (व्यक्तिगत) आधार पर, अर्थात् केवल संबंधित व्यक्तिगत आवेदकों के संबंध में, कारणयुक्त (स्पीकिंग) आदेश जारी करते हुये लागू किया जाये, बशर्ते कि प्रकरण के तथ्य माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13225/2010 में एम. सुब्रमणियम प्रकरण में दिनांक 06.09.2010 को पारित आदेश से आच्छादित मामले के समान हों, जिसके विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) निरस्त की जा चुकी है।

Since, the issue involved in the matter is related to the policy, the Board after examination, vide letter F. No. A-23011/44/2020-Ad IIA-(Pt.2) dated 03.09.2025, have directed to implement the aforesaid Order of the Tribunal in respect of the individual applicants on in personam basis only, by way of issuing the speaking order provided that the case is similar to the case covered in the Hon'ble Madras High Court order dated 06.09.2010 in W.P. No 13225/2010 passed in M. Subramaniam case against which SLP was dismissed.

7. मामले की जांच करते समय, यह देखा गया कि, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के आदेश में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर, श्री एम. सुब्रमण्यम ने 16.01.1992 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में निरीक्षक के रूप में सेवा में प्रवेश किया। पहले वित्तीय उन्नयन का लाभ याचिकाकर्ता को ACP योजना के आधार पर दिनांक 01.01.2004 से वेतनमान रु.7500-250-12000 (छठे केंद्रीय वेतन आयोग में PB-2 में ग्रेड पे रु.4800/- के रूप में संशोधित और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में स्तर-8 रु.47600-151100 में पुनः संशोधित) में प्रदान किया गया। वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक के समकक्ष वेतनमान रु.7500-250-12000 में वेतन प्राप्त कर रहे थे। श्री एम. सुब्रमण्यम ने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ में मूल आवेदन संख्या 167/2009 दायर की, जिसे अधिकरण ने दिनांक 19.04.2010 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

While examining the case, it is observed, on the basis of facts mentioned in the aforesaid Order dated 06.09.2010 of the Hon'ble Madras

High Court, that Shri M. Subramaniam joined service as Inspector of Central Excise on 16.01.1992. The benefit of first financial up-gradation was granted to the applicant with effect from 01.01.2004 in the pay scale of Rs. 7500-250-12000 (revised as grade pay of Rs. 4800/- in PB-2 in 6th CPC and further revised as Level-8 Rs. 47600- 151100 in 7th CPC) on the basis of the ACP Scheme. He was drawing the pay scale of Rs. 7500-250-12000 being the pay scale of Superintendent of Central Excise. Shri M Subramaniam filed O.A. No. 167/2009 in the Hon'ble CAT, Madras Bench. The Tribunal rejected the same vide Order dated 19.04.2010.

7.1 अधिकरण के आदेश के विरुद्ध, श्री सुब्रमण्यम ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13225/2010 दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.09.2010 के अपने आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और मूल आवेदन संख्या 167/2009 में दिनांक 19.04.2010 के माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 29.08.2008 के संकल्प के अनुसार 01.01.2008 से ग्रेड पे ₹5400/- का लाभ दिया जाये। इसके अतिरिक्त, भारत संघ द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ दायर सिविल अपील संख्या 8883/2011 और समीक्षा याचिका को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

Against the Order of the Tribunal, Shri Subramaniam filed Writ Petition No. 13225/2010 before the Hon'ble High Court of Madras. The Hon'ble Court vide Order dated 06.09.2010 allowed the Writ Petition filed by the applicant and set aside the order of the Hon'ble CAT, Madras Bench dated 19.04.2010 passed in the O.A. No. 167/2009. The Hon'ble High Court ordered to extend the benefit of Grade Pay of Rs 5400/- to the petitioner from 01.01.2008 as per the Resolution dated 29.08.2010 (correct date 29.08.2008). Further, the Civil Appeal No 8883/2011 and Review Petition filed by UOI against the said order was also dismissed by the Hon'ble Supreme Court vide Order dated 10.10.2017.

8. आवेदक के संबंध में मामले के तथ्य जांचे गये हैं। विभाग के अभिलेखों के आधार पर, उनके सेवा विवरण निम्नानुसार हैं:-

The facts of the case in respect of applicant have been examined. On the basis of the records of the Department, the service particulars in respect of him are as under:-

Table

S. No.	Name of the Officer & Date of Birth (Shri)	Designat-ion	Date of Joining as Inspector in the Department in pre-revised scale of pay Rs. 5500-9000 (revised as Rs. 6500-10500) corresponding to Grade Pay Rs. 4600/- in PB-2 in pay band Rs. 9300-34800. (further revised as Level-7 in pay matrix Rs. 44900-142400)	Date of grant of pre-revised scale of pay Rs. 6500-10500 (revised as Rs. 7500-12000) corresponding to Grade Pay Rs. 4800/- in PB-2 in pay band Rs. 9300-34800 in 6th CPC. (further revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100 in 7th CPC) by virtue of ACP Scheme (1st Financial Upgradation)	Date of promotion to the grade of Superintendent in pre-revised scale of pay Rs. 6500-10500 (revised as Rs. 7500-12000) corresponding to Grade Pay Rs. 4800/- in PB-2 in pay band Rs. 9300-34800 in 6th CPC. (further revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100 in 7th CPC)	Date of grant of Non-Functional Upgradation to the pre-revised scale of Rs. 8000-13500 corresponding to Grade Pay Rs. 5400/- in PB-2 in pay band Rs. 9300-34800 (further revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800), counting 4 years from the date of promotion to the grade of Superintendent in pre-revised scale of pay Rs. 6500-10500 (revised as Rs. 7500-12000) corresponding to Grade Pay Rs. 4800/- in PB-2 in pay band Rs. 9300-34800 (further revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100)	Revised date of grant of Non-Functional Upgradation to the pre-revised scale of Rs. 8000-13500 corresponding to Grade Pay Rs. 5400/- in PB-2 in pay band Rs. 9300-34800 (further revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800), counting 4 years from the date of grant of pre-revised scale of pay Rs. 6500-10500 (revised as Rs. 7500-12000) corresponding to Grade Pay Rs. 4800/- in PB-2 in pay band Rs. 9300-34800 (further revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100) (as shown in Column No. 5), by virtue of ACP Scheme
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	Gajendra Singh Newari (06.11.1965)	Asstt. Commi-ssioner (Retired)	23.03.1992	22.03.2004	30.08.2006	30.08.2010	22.03.2008

जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त मूल आवेदन (O.A.) के आवेदक को सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना के अंतर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹6500–10500 (संशोधित ₹7500–12000) में प्रदान किया गया था, जो छठे

वेतन आयोग (6th CPC) में वेतन बैंड ₹9300–34800 (PB-2) में ग्रेड पे ₹4800/- के समतुल्य है (जिसे आगे सातवें वेतन आयोग (7th CPC) में वेतन मैट्रिक्स ₹47,600–1,51,100 के लेवल-8 के रूप में संशोधित किया गया)। यह लाभ उपरोक्त तालिका में उनके नाम के समक्ष स्तंभ संख्या 5 में उल्लिखित तिथि से प्रभावी किया गया था। अब वह, पी.बी.-2 में ग्रेड पे ₹4800/- (सातवें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स ₹47,600–1,51,100 के लेवल-8 के रूप में संशोधित) पर 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, पी.बी.-2 में ₹5400/- के गैर-कार्यात्मक ग्रेड पे (सातवें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स ₹53,100–1,67,800 के लेवल-9 के रूप में संशोधित) का लाभ प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं, जो कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के निर्णय (डब्ल्यूपी संख्या 13225/2010, प्रकरण: एम. सुब्रमण्यम) के अनुसार है।

On examination, it is found that the applicant of the aforesaid O.A. had been granted 1st financial upgradation under ACP Scheme in pre-revised scale of pay Rs. 6500-10500 (revised as Rs. 7500-12000) corresponding to Grade Pay Rs. 4800/- in PB-2 in pay band Rs. 9300-34800 in 6th CPC (Further, revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47,600-1,51,100 in 7th CPC) w.e.f. from the date mentioned in column no. 5 against his name in above table. Now, he is seeking the benefit of non-functional grade pay of Rs 5400/- in PB-2 (revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53,100-1,67,800 in 7th CPC) on completion of 4 years' service in the grade pay of Rs. 4800/- in PB-2 (revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47,600-1,51,100) in terms of judgement dated 06.09.2010 of the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 13225/2010 in the case of M. Subramaniam.

माननीय न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 (सुप्रा) के आदेश के अनुसार, श्री एम. सुब्रमण्यम को सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना के तहत 01.01.2004 से वेतनमान ₹7500-12000 प्रदान किया गया और उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 01.01.2008 से ग्रेड पे ₹5400/- का लाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया।

As per the Hon'ble Court's Order dated 06.09.2010 (supra), Shri M. Subramaniam was granted the pay scale of Rs. 7500-12000 (revised as Grade Pay of Rs. 4800/- in PB-2 in 6th CPC) under ACP Scheme on 01.01.2004 and sought benefits of grade pay of Rs 5400/- w.e.f. 01.01.2008 i.e. on completion of 4 years service in the grade pay of Rs 4800/-in PB-2 granted by virtue of ACP Scheme.

9. माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के आदेश, डब्ल्यू.पी. संख्या 13225/2010 (एम. सुब्रमणियम प्रकरण) के पैरा 8 में, जिसके विरुद्ध दायर एसएलपी खारिज कर दी गई थी, यह कहा गया है कि "यदि किसी अधिकारी ने 01.01.2006 को या उससे

पहले 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, तो उसे 01.01.2006 से गैर-कार्यात्मक उन्नयन (Non-Functional Upgradation) प्रदान किया जायेगा और यदि कोई अधिकारी 01.01.2006 के बाद किसी तिथि को 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करता है, तो उसे उसी तिथि से गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया जायेगा, जिस तिथि को वह ₹7500–12000 (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करता है।" उपरोक्त के दृष्टिगत, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के आदेश (रिट याचिका सं. 13225/2010, एम. सुब्रमण्यम मामले) के तात्त्विक अनुप्रयोग के आधार पर, यह पाया गया कि पैरा 8 में वर्णित तालिका में नामित अधिकारी, जो कि उपरोक्त मूल आवेदन में आवेदक भी है, PB-2 में ग्रेड पे ₹5400/- (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-9 ₹53100-167800 में संशोधित) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन का हकदार हैं, जब उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 ₹47,600-1,51,100 में संशोधित) में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

The para 8 of the Hon'ble High Court Order dated 06.09.2010 in W.P. No. 13225/2010 passed in M. Subramaniam case against which SLP was dismissed states that "if an officer has completed 4-years on 1.1.2006 or earlier, he will be given the nonfunctional upgradation with effect from 1.1.2006 and if the officer completes 4-year on a date after 1.1.2006, he will be given non-functional upgradation from such date on which he completes 4-year in the pay scale of Rs.7500-12000 (pre revised)." In view of above, applying the ratio of the Order dated 06.09.2010 of the Hon'ble Madras High Court in W.P. No. 13225/2010 in M. Subramaniam case, it is observed that the aforesaid officer as mentioned in the table in para 8, who ia also the applicant of aforesaid O.A., is entitled to Non-Functional Upgradation to the grade pay of Rs. 5400/- in PB-2 (revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800 in 7th CPC) on completion of 4 years service in the grade pay of Rs. 4800/- in PB-2 in 6th CPC (revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100 in 7th CPC).

10. अतः, उपरोक्त पैरा 8 की तालिका में उल्लिखित अधिकारी को, पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹6,500–10,500 (₹7,500-12,000 में संशोधित) के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर, गैर-कार्यात्मक उन्नयन (Non-Functional Upgradation) प्रदान किया जाता है। यह उन्नयन पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹8,000–13,500, जो संशोधित वेतन संरचना ₹9,300–34,800 में ग्रेड पे ₹5,400 (PB-2) के समकक्ष है (जो आगे चलकर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9 ₹53,100–1,67,800 के रूप में संशोधित किया गया है), में दिया जाता है। उक्त उन्नयन, पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹6,500–10,500, जो संशोधित वेतन संरचना ₹9,300–34,800 में ग्रेड पे ₹4,800 (PB-2) के समकक्ष है (जो आगे चलकर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-

8 ₹47,600–1,51,100 के रूप में संशोधित किया गया है) में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर, उपरोक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 8 में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई संशोधित तिथि से प्रभावी होगा।

Accordingly, the officer named in the Table in para 8 above, is granted Non-Functional Upgradation to the pre-revised scale of Rs. 8,000-13,500 corresponding to Grade Pay Rs. 5,400/- in PB-2 in pay band Rs. 9,300-34,800 (further revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53,100-1,67,800), on completion of 4 years of regular service in pre-revised scale of pay Rs. 6,500-10,500 (revised as Rs. 7,500-12,000) corresponding to Grade Pay Rs. 4,800/- in PB-2 in pay band Rs. 9,300-34,800 (further revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47,600-1,51,100), from the revised date shown against his name in Column No. 8 of the aforesaid Table.

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

Digitally signed by
DINESH SINGH DEWAL
Date: 25-05-2026
13:11:15

(दिनेश सिंह देवल/Dinesh Singh Dewal)
अपर आयुक्त/Additional Commissioner

फा.सं.- GCCO/II/26/10/2025-ADMN दिनांक:-ई-हस्ताक्षर के अनुसार
F No.:- GCCO/II/26/10/2025-ADMN Date:-As per E-sign

सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित:-
Copy for information and necessary action to:-

1. संबंधित अधिकारी/Officer Concerned.
2. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) जोधपुर |
   The Commissioner, Customs (Preventive) Jodhpur.
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, जयपुर/The PAO, CGST & Customs, Jaipur.
4. मुख्य लेखाधिकारी/ प्र. अधिकारी (डी.डी.ओ.) सीमा शुल्क (निवारक) जोधपुर |
   The CAO /AO (DDO), Customs (Preventive) Jodhpur.
5. सेवा पुस्तिका/गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड |
   Service Book / Guard file / Notice Board.
6. क्षेत्रीय वेबसाइट पर आदेश की प्रति अपलोड करने के लिए वेबमास्टर से अनुरोध है।
   Webmaster for uploading a copy of the order on Zonal Website.